वॉल्यूम 32, सं. 3, जनवरी, 2024

# इंफोमेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लोक भवन, लखनऊ में यूपी बोर्ड स्कूलों के लिए "ऑनलाइन मान्यता पोर्टल" लॉन्च किया

## माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यूपीएसईबी के लिए ऑनलाइन मान्यता पोर्टल लॉन्च किया

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने, 13 अक्टूबर 2023 को यूपी बोर्ड स्कूलों के लिए "ऑनलाइन मान्यता पोर्टल" का उद्घाटन किया, जो शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक भवन, लखनऊ में आयोजित, यह लॉन्च उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों के लिए मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का वादा करता है।

इस पोर्टल का सार इसके एंड-टू-एंड सॉफ़्टवेयर समाधान में निहित है, जो मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूल प्रबंधन की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह नवोन्मेषी मंच आवेदन प्रक्रिया शुरू करता है, जहां स्कूल प्रबंधन निर्बाध रूप से अपनी मान्यता यात्रा शुरू कर सकते हैं। आवेदन पूरा होने और राजकोष (यू.पी. ट्रेजरी ऑनलाइन सिस्टम) के माध्यम से फीस का भुगतान करने पर, प्रगति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) लॉगिन के डैशबोर्ड पर दिखाई देती है। इस पोर्टल की एक उल्लेखनीय विशेषता ट्रेजरी, राजस्व, अग्निशमन और अन्य सहित विभिन्न बाहरी विभागों के साथ इसका एकीकरण है। एक बार आवेदन उनके संबंधित लॉगिन पर दिखाई देने के बाद प्रत्येक विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की ऑनलाइन पीढ़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीआईओएस योग्यता मानदंडों के आधार पर प्रत्येक आवेदन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है और संबंधित 11 बाहरी विभागों से प्राप्त ऑनलाइन एनओसी का सत्यापन करता है।

डीआईओएस द्वारा अनुमोदन पर, एप्लिकेशन बोर्ड के लॉगिन के माध्यम से विभागीय पदानुक्रम के माध्यम से निर्बाध रूप से नेविगेट करता है और क्षेत्रीय कार्यालय में आगे बढ़ता है। स्वीकृत आवेदन फिर मान्यता की अंतिम मुहर के लिए शीर्ष राज्य सरकार के पास जाते हैं, इस प्रकार यूपी बोर्ड के तहत स्कूलों को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उद्घाटन समारोह में माननीय श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति देखी गई, जो इस परिवर्तनकारी पहल के महत्व और गंभीरता को दर्शाता है।

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, श्री आर.एच. खान, वैज्ञानिक-जी और डीडीजी के मार्गदर्शन में "ऑनलाइन मान्यता पोर्टल" के समय पर विकास और होस्टिंग के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी यूपी) को आभार व्यक्त किया गया।

**- परविज इस्लाम, उत्तर प्रदेश**

# त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा में ई-कैबिनेट लॉन्च के साथ डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया

त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. माणिक साहा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से 27 सितंबर, 2023 को अगरतला में एनआईसी के ईकैबिनेट समाधान की शुरुआत करते हुए

त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार, 27 सितंबर 2023 को अगरतला में राज्य में कैबिनेट बैठकों के स्वचालन के लिए एनआईसी का ईकैबिनेट समाधान लॉन्च किया। ईकैबिनेट प्रणाली कैबिनेट गतिविधियों को डिजिटल बनाती है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्मार्ट गवर्नेंस को सक्षम करके कागज रहित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है।

इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई-कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। राज्य में भविष्य की सभी कैबिनेट बैठकें कागज रहित होंगी, इस प्रक्रिया में कार्बन पदचिह्न और पर्यावरणीय गिरावट को कम किया जाएगा, जिसमें मंत्री और नौकरशाह टैबलेट का उपयोग करेंगे।

पहली ई-कैबिनेट बैठक में, सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 160 करोड़ रुपये का ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसने पहले सरकार को कम ब्याज दरों पर आसान ऋण प्रदान किया था और कई विकासात्मक परियोजनाओं में इसके साथ भागीदारी की थी। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि नए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) फंड का उपयोग पर्यटन और शहरी विकास विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और स्थायी आजीविका सृजन की पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट उत्तराखंड में शुरू किए गए समान मॉडल का अनुसरण करेगी। ई-कैबिनेट प्रणाली एनआईसी के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से ई-शासन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की विकास यात्रा राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित होगी। इस बदलाव से पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने आगे बताया कि ई-कैबिनेट ऐप में दिनांक और समय के साथ चिह्नित कैबिनेट ज्ञापनों को अपलोड करने की सुविधा होगी और मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव और अन्य अधिकारी उनकी ऑनलाइन समीक्षा और अनुमोदन कर सकेंगे।

सरकार ने उन विभागों को मानद प्रशस्तियाँ भी प्रदान कीं जो 100 प्रतिशत ई-ऑफिस अपनाने के हिस्से के रूप में कागज रहित हो गए हैं। जिन 94 सरकारी विभागों को पेपरलेस संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें से 41 को बुधवार को प्रशस्ति मिली।

**- चैताली भट्टाचार्य, त्रिपुरा**

# गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद नागरिकों की सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री राहत कोष' पोर्टल शुरू किया

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल ने गुजरात में 'मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल' का अनावरण किया है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) गुजरात द्वारा विकसित एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पहल नागरिकों को इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाओं के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन दान करने की अनुमति देती है।

दानदाता यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या क्यूआर कोड के माध्यम से बुनियादी विवरण और संपूर्ण भुगतान प्रदान करते हैं। भुगतान करने पर, उन्हें तत्काल ई-रसीदें, 80-जी प्रमाणपत्र और मुख्यमंत्री से एक व्यक्तिगत प्रशंसा प्रमाणपत्र प्राप्त होता है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित होता है।

सितंबर 2021 से अब तक, सरकार ने गंभीर बीमारियों के लिए 30.81 करोड़ रुपये और दुर्घटना पीड़ितों के लिए 18.85 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये योगदान आपदाओं, गंभीर चिकित्सा उपचार और घातक सड़क दुर्घटनाओं में सहायता करते हैं। गांधीनगर में लॉन्च के दौरान महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने दान प्राप्तियों के डिजिटलीकरण का समर्थन किया, जिसमें राज्य राहत आयुक्त और भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

यह पोर्टल वैश्विक व्यक्तियों को संकट में फंसे लोगों की सहायता करने और एकजुटता बनाए रखने के सरकार के मिशन के साथ जुड़कर निर्बाध रूप से समर्थन देने का अधिकार देता है।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल ने गांधीनगर में 'गुजरात में मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल' का अनावरण किया, ताकि लोग आसानी से सरकारी सहायता मिशनों में सहायता प्रदान कर सकें

**- अमित दिनकरभाई शाह, गुजरात**

# माननीय उप राज्यपाल दिल्ली ने दिल्ली में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वीसीआईएमएस लॉन्च किया

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने सतर्कता विभाग, जीएनसीटीडी की सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) का शुभारंभ किया। एनआईसी के सहयोग से विकसित यह प्रणाली नागरिकों से ऑनलाइन सतर्कता संबंधी शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाती है।

वीसीआईएमएस पोर्टल, https://vcims.delhi.gov.in के माध्यम से सुलभ, नागरिकों को निर्बाध रूप से शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने वाला एक मजबूत मंच है। विशेष रूप से, यह प्रणाली शिकायतकर्ताओं को पीडीएफ, ऑडियो या वीडियो फ़ाइलों के रूप में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जिससे व्यक्तियों को अपनी शिकायतों को व्यापक रूप से व्यक्त करने का अधिकार मिलता है।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की क्षमता है। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस अलर्ट प्राप्त होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपनी शिकायतों की प्रगति के बारे में अपडेट रहें, पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिले।

यह पहल भ्रष्टाचार से निपटने में एक बड़ी उपलब्धि है, जो नागरिकों को अपनी पहचान उजागर किए बिना शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल की पेशकश करती है। प्रणाली शिकायतकर्ताओं की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, उन्हें किसी भी संभावित प्रभाव से बचाता है, जबकि शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों तक कुशलतापूर्वक संप्रेषित करता है।

माननीय उपराज्यपाल ने राज निवास में लॉन्च के दौरान वीसीआईएमएस की विशिष्टता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे यह ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की दिशा

दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने सतर्कता विभाग, जीएनसीटीडी की सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) का शुभारंभ किया

में एक महत्वपूर्ण कदम है। सक्सेना ने जोर देकर कहा कि पोर्टल विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों को कवर करता है, जिससे दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ शिकायतों की संभावना कम हो जाती है।

संक्षेप में, वीसीआईएमएस का शुभारंभ अपने नागरिकों को सशक्त बनाने, उनकी पहचान की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज को सुनिश्चित करने की दिल्ली की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह प्रगतिशील कदम एक भ्रष्टाचार-मुक्त समाज को बढ़ावा देने की दृष्टि से मेल खाता है, जहां ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाता है, और गलत कामों को तेजी से संबोधित किया जाता है।

**- सूचना विज्ञान न्यू डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय**

पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन, व्यापक डेटा प्रबंधन के लिए एकीकृत डेटा हब (यूडीएच) का उद्घाटन करते हुए

# माननीय उपराज्यपाल पुडुचेरी ने व्यापक डेटा प्रबंधन के लिए एकीकृत डेटा हब का उद्घाटन किया

पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) पुडुचेरी द्वारा विकसित यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच) का उद्घाटन किया। यूडीएच एक व्यापक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो 23 विभागों और 140 कल्याणकारी योजनाओं से डेटा को समेकित करता है, लाभार्थी प्रोफाइल में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यह केंद्रीकृत भंडार विभिन्न विभागों और योजनाओं से लाभार्थियों के विवरण को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है, जिससे स्थानीय निकायों से जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर नियमित अपडेट सुनिश्चित होता है। यूडीएच कल्याण विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, डिडुप्लीकेशन, सत्यापन, क्रॉस-रेफरेंसिंग, आधार डेटा वॉल्ट के साथ एकीकरण और जन्म/मृत्यु अधिसूचना जैसी सुविधाओं को नियोजित करने में सहायता करता है।

श्री एस राजशेखरन, एसआईओ पुडुचेरी ने यूडीएच के प्रभाव पर जोर दिया और कल्याण विभागों के लिए इसकी विशेषताओं और सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुव्यवस्थित सत्यापन के लिए वेब एपीआई सेवाओं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिलॉकर के एकीकरण पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, श्री अरुलराज वरिष्ठ, निदेशक (आईटी) ने लाभार्थी अपडेट के दौरान पोर्टल के डेटा जीवन चक्र को समझाते हुए यूडीएच के चरण I और II सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की।

यूडीएच कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के लिए वृद्धिशील डेटा एकत्र करने, डी-डुप्लीकेशन और क्रॉस-रेफरेंसिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक विवरण एकत्र करने, सटीक और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**- वी. गोपी स्वामीनाथन, पुडुचेरी**

# हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारी के लिए स्कूल सुरक्षा एप्लिकेशन लॉन्च किया

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वार्षिक जन जागरूकता अभियान - समर्थ का 13वां संस्करण एक महत्वपूर्ण लॉन्च का मंच बन गया। समर्थ 2023 के दौरान, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित स्कूल सुरक्षा एप्लिकेशन का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में आपदा तैयारियों को मजबूत करना है।

इस कार्यक्रम में श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राज्य राजस्व मंत्री, श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव, श्री ओसी शर्मा, प्रमुख सचिव (राजस्व), श्री अजय सिंह चहल, डीडीजी और एसआईओ हिमाचल प्रदेश, श्री डी.सी. राणा, निदेशक एसडीएमए और विशेष सचिव (राजस्व), श्री संदीप सूद, वैज्ञानिक-एफ और समूह प्रमुख, और श्री संजय कुमार, वैज्ञानिक-ई सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

स्कूल सुरक्षा एप्लिकेशन, जो वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म दोनों के रूप में उपलब्ध है, का उद्देश्य राज्य भर के स्कूलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

वार्षिक डीएमपी निर्माण को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, मोबाइल ऐप सहज और स्वचालित योजना तैयारी के लिए एक मानक टेम्पलेट प्रदान करता है। प्रत्येक स्कूल के नोडल अधिकारी ऐप में लॉग इन करते हैं, योजना बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी जोड़ते हैं। ऐप ब्लॉक, जिला और राज्य प्रशासकों को योजना तैयारी की प्रगति की निर्बाध रूप से निगरानी करने की अनुमति देता है।

पहल के एक भाग के रूप में, चयनित पायलट स्कूलों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए उनकी वार्षिक स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान किया गया था। असाधारण प्रदर्शन के सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वार्षिक जन जागरूकता अभियान – समर्थ के 13वें संस्करण के दौरान आपदा तैयारी के लिए स्कूल सुरक्षा एप्लिकेशन का शुभारंभ किया

50,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।

स्कूल सुरक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएसएमआईएस) एक वेब एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप द्वारा पूरक है, जो एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध है। स्कूल इन प्लेटफार्मों तक पहुंचने के लिए अपने यूडीआईएसई कोड को यूजर आईडी के रूप में उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर स्कूलों को अपने डीएमपी विकसित करने में सक्षम बनाता है, जबकि राज्य, जिला और ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न स्कूलों में आपदा तैयारियों की निगरानी करने की अनुमति देता है।

यह तकनीकी हस्तक्षेप पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सुरक्षा उपायों और आपदा तैयारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उच्च अधिकारियों द्वारा तैयारियों के स्तर की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की अनुमति मिलती है।

**- संदीप सूद, हिमाचल प्रदेश**

# माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने पेपरलेस पंजाब विधानसभा के लिए NeVA लॉन्च किया

माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने 21 सितंबर, 2023, को पंजाब विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) का उद्घाटन किया, जो विधायकों को सशक्त बनाने और कागज रहित विधानसभा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री, विधायक और प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान, अध्यक्ष सरदार कुलतार सिंह संधवान ने समय पर एनईवीए कार्यान्वयन में एनआईसी पंजाब के प्रयासों को स्वीकार किया और कागजरहित सदन कार्य, सदन की समितियों के आंतरिक कामकाज और ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन से शुरू करके सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर समाधान की कल्पना की।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एनईवीए लॉन्च किया और पंजाब में इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए चार अतिरिक्त पहलों का अनावरण किया। इन पहलों में दो दिवसीय सम्मेलन-सह-कार्यशाला, एनईवीए पंजाब के लिए एक विजन ब्रोशर, एनआईसी पंजाब द्वारा विकसित नई पंजाब विधान सभा वेबसाइट, एनईवीए 2.0 कार्यक्षमताएं, एनईवीए सेवा केंद्र और पंजाब विधान सभा सचिवालय में एक डिजिटल विंग शामिल हैं।

एसआईओ और डीडीजी विवेक वर्मा ने एनईवीए के प्रयासों, चुनौतियों और इसके कार्यान्वयन में एनआईसी पंजाब, निकसी और डीओजीआर पंजाब की भूमिकाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें परियोजना की वर्तमान स्थिति और विधानसभा परिसर में हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई के एकीकरण का विवरण दिया गया।

वरिष्ठ निदेशक (आईटी) धर्मेश कुमार ने सदन, सदन समितियों और ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की रूपरेखा तैयार की, जिसमें इन क्षेत्रों के आंतरिक कामकाज के लिए पूरक एनईवीए 2.0 पर जोर दिया गया, जो एक व्यापक सॉफ्टवेयर समाधान पेश करता है। एनआईसी-एमओपीए के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) संजीव ने विभिन्न भारतीय राज्यों में एनईवीए को लागू करने में दिशानिर्देश और अनुभव साझा किए। विशेष रूप से, एनआईसी पंजाब राज्य इकाई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनईवीए सम्मेलन में भाग लिया और योगदान दिया।

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ 21 सितंबर, 2023 को पंजाब विधानसभा में पेपरलेस पंजाब विधानसभा के लिए NeVA का शुभारंभ करते हुए

मुख्यमंत्री ने इस पहल को क्रांतिकारी, विधायी जवाबदेही बढ़ाने वाली पहल बताया और एक पूर्ण सॉफ्टवेयर समाधान के रूप में एनईवीए के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों के पंजाब के अग्रणी लॉन्च पर गर्व किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा के डिजिटलीकरण से जनता की चिंताओं को संबोधित करने में विधायकों की दक्षता बढ़ेगी, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्यों द्वारा इसके उपयोग की कल्पना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस कदम को एक नए युग की शुरुआत बताया, जिससे कागज रहित विधानसभा और पारदर्शी, जवाबदेह प्रक्रियाएं सुनिश्चित होंगी, जिससे विधायक सशक्त होंगे। उन्होंने जनहित के लिए आगे भी प्रयास करने का संकल्प लिया। विशेष रूप से, डिजिटल कार्यक्षमता को आगे बढ़ाते हुए मंत्रियों और विधायकों को आईपैड वितरित किए गए। उपाध्यक्ष सरदार जय कृष्ण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया।

**- परमिंदर कौर, पंजाब**

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news